VOL. III—NO. 19.

THE BIHAR LEGISLATIVE ASSEMBLY DEBATES

Friday, the 10th October, 1947.

Proceedings of the Bihar Legislative Assembly assembled under the provisions of the Government of India Act, 1935.

The Assembly met in the Assembly Chamber at Ranchi, on Friday, the 10th October, 1947, at 2 P. M., the Hon'ble the Speaker, Mr. Vindhyeshvwari Prasada Varma, in the Chair.

WELCOME TO THE HON'BLE MR. ANUGRAH NARAYAN SINHA ON HIS RETURN FROM GENEVA.

The Hon'ble the SPEAKER : The House is having the Hon'ble Mr. Anugrah Narayan Sinha in its midst to-day on his safe return from Mission at Geneva as Leader of the Indian Food Delegation. (*Cheers.*) We welcome him back and feel highly gratified that he successfully led the Mission and paid visits to other countries in Europe.

The Hon'ble Mr. ANUGRAH NARAYAN SINHA : I thank you, Sir, for the kind words that you have expressed. I hope I have benefited by the journey and I feel that I shall be able to serve my people much better than I did before.

Hon'ble Members : Long live the Hon'ble Mr Anugrah Narayan Sinha.

QUESTIONS AND ANSWERS.

MOTOR CAR ACCIDENT IN MONGHYR ON THE MONGHYR-PIPARPANTI ROAD.

***52. Mr. MOSAHEB SINHA :** Will the Hon'ble the Prime Minister be pleased to state—

(*a*) whether it is a fact that a serious motor accident took place on the Monghyr-Piparpanti Road in the last week of April, 1946, in which a beautiful little son of the poor clerk of Monghyr District Inspector of Schools' Office was crushed to death under the car of Rai Bahadur S. N. Roy, the present Additional District Magistrate of Monghyr ;

(*b*) whether it is a fact that car was being driven by the second son of Rai Bahadur at the time of accident who possesses no licence ;

*In absence of the questioner, the answer was given at the request of Mr. Birendra Bahadur Sinha.

The Hon'ble the Speaker:— The question is :

That in clause 7 of the Bill, in sub-clause (2) after the word " absence " in the last line in which the word occurs, the words " without sufficient cause " be inserted.

The motion was adopted.

The Hon'ble the Speaker : The question is :

That in clause 15 of the Bill, in sub-clause (2)—(i) after item (a) the following item be inserted, namely :—

" (b) the prescription of any other proof of miscarriage referred to in sub-section (4) of section 4 or birth to child referred to in sub-section (4) of section 5 ; ".

(ii) items (b) to (e) be re-lettered as items (c) to (f) respectively, and

(iii) the word ' and ' at the end of item (f) as so re-letterred and item (f) as originally lettered be omitted.

The motion was adopted.

Secretary will now convey the message to the Council that the Assembly has concurred in the amendments made by the Council.

THE BIHAR SUGAR FACTORIES CONTROL (SECOND AMENDMENT), BILL, 1947 (BILL NO. 39 OF 1947)

The Hon'ble Dr. Saiyid Mahmud : Sir, I beg to move :

That the Bihar Sugar Factories Control (Second Amendment) Bill, 1947, be taken into consideration.

حضور والا - میں چند لفظ کہنا چاھتا ھوں مجھے یہ معلوم ھوا ھے کہ ممبروں کی خواھش ھے جیسا کہ ان کے speeches سے پہلے ظاھر ھوا کہ شوگر فیکٹری کا رول جو سنہ ۱۹۳۷ ع میں بنا تھا اسمیں تھوڑا بہت املاق ملت ھوا ھے لیکن اسکو کئی برس ھوگئے اسلئے میں انکو پھر سے revise کرنے کے پہلے اور ممبروں کے اطلاع

کیلئے یہ قدم اتھایا ھے اور اس محکمہ کو بھی کہا تھا کہ اسکے revise کرنیکی کوشش کیجائے لیکن ممبروں کی آج خواھش معلوم ھونے کے بعد میں نے ایک کمیٹی مقرر کی ھے جسمیں طوگر فیکٹری کے نمائندہ بھی ھوں اور ممبران اسمبلی بھی ھوں جو جلد از جلد اس ایکٹ کے تمام رول کو جو پہلے بنا دئے گئے ھیں انکو دیکھکر جو امنڈ منٹ مناسب سمجھیں اسکی اطلاع گورنمنٹ کو دیں اسکو غور کرکے پھر ایک امنڈنگ بل لاکر آپکے سامنے پیش کریں جہانتک مرا خیال ھے اس بیان سے جو آپکا مقصد امنڈ منٹ سے ھے پورا ھو جائیگا اسلئے میں نہیں سمجھتا ھوں کہ اس امنڈنگ بل کو جو بالکل ایک چھوتی سی چیز پورے ایکٹ کو cover نہیں کرتا ھے ترمیم کی ضرورت باقی رھتی ھے بہر حال جو صاحب amendment کر رھے ھیں انکے خواھش پر منحصر ھے -

The Hon'ble the Speaker : The question is :

That the Bihar Sugar Factories Control (Second Amendment) Bill, 1947, be taken into consideration.

The motion was adopted.

The Hon'ble the Speaker :—

I now take up the bill, clause by clause.

Mr. Jhulan Sinha : स्पीकर महोदय, मेरे नाम में ६,७ संशोधन हैं। माननीय मिनिस्टर ने अभी जो बयान दिया है, उससे मालूम होता है कि वह पूरे ऐक्ट और रूल्स को रिवाइज (Revise) करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक कमिटी बनाने का तय कर लिया है। ऐसी हालत में मैंने जो संशोधन दिए हैं उन्हें मुझे कमिटी के सामने पेश करने पड़ेंगे। मेरे संशोधनों का मंशा यह है कि अभी जो ऊख का समय आ रहा है उसमें ऊख उपजानेवालों में sense of security होनी चाहिए, जिससे ऊख के उद्योग में depression नहीं आने पावे और वह आगे बढ़ सके। मेरे संशोधन तो बाद में बजट सेशन में भी पेश हो सकते हैं। लेकिन ऊख के उद्योग के संबंध में मुझे एक-दो बातें कहनी हैं जिनके संबंध में देर होने से बहुत नुकसान होगा।

The Ho'nble the Speaker : अगर इस तरह की बातें कहनी हैं तो क्लाजों के पास होने के बाद इन बातों का कहना ज्यादा मौजूं होगा।

The Hon'ble the Speaker:—The question is :

That clauses 2 to 22, do stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clauses 2 to 22, were added to the Bill.

The Hon'ble the Speaker : The question is :

That clause 1 do stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 1 was added to the Bill.

The Hon'ble the Speaker : The question is :

That the Preamble be added to the Bill.

The motion was adopted.

The preamble was added to the Bill.

The Hon'ble the Speaker : The question is :

That the Title be added to the Bill.

The motion was adopted.

The Title was added to the Bill.

The Hon'ble the Speaker : The question is ;

That the Title be added to the Bill.

The motion was adopted.

The Title was added to the Bill.

The Hon'ble Dr. Saiyid Mahmud : Sir, I beg to move :

That the Bihar Sugar Factories Control (Second Amendment) Bill, 1947 be passed.

Mr. Jhulan Sinha : सभापतिजी, जैसा मैंने अभी कहा है, मैं कुछ जरूरी बातों की तरफ मिनिस्टर साहब का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। ऊख का व्यवसाय ऐसी हालत में है कि यदि इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया और growers as a whole को Sense of security नहीं हुई तो यह व्यवसाय बहुत जल्द खतम हो जायगा। हमलोग देख रहे हैं कि इस व्यवसाय की

हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है और इसे तुरत बचाने की जरूरत है। मैंने अपने संशोधन इसीलिए दिये थे। लेकिन एक बात ऐसी है जिसके संबंध में देर नहीं की जा सकती है। ऊख पेरने का समय एक दो महीना में शुरू हो जायगा। ऊख की जो कीमत गृहस्थों को मिलती है वह विचारणीय है। जो कीमत अभी उन्हें मिल रही है वह काफी नाकाफी है। मैं मिनिस्टर साहब का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूँ। हमलोगों ने हिसाब करके देखा है और उसके मुताबिक ऊख की कीमत दो रुपए फी मन से कम नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में सरकार इसलिए नहीं कीमत बढ़ा रही है कि ऐसा करने से inflation हो जायगा। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक मुहकमा में inflation को रोकने से inflation नहीं रुक सकता है। ऊख की कीमत नहीं बढ़ाने का नतीजा यह होता है कि एक तबके के लोग victimise हो जाते हैं। अगर आप anti inflation measures को लागू करना चाहते हैं तो आप इसे हर मुहकमे में लागू कीजिए। मेरी प्रार्थना यह है कि आप ऊख उपजाने वालों का खर्च देखकर ऊख की कीमत दो रुपये फी मन कर दीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो इस कंट्रोल ऐक्ट के बावजूद भी यह इन्डस्ट्री खतम हो जायगी। आशा है इस बात की ओर मिनिस्टर साहब ध्यान देंगे। मैं यह भी आशा करता हूँ कि इस चीज को मिनिस्टर साहब बिहार और यू० पी० की सम्मिलित कान्फ्रेंस या भारत सरकार के सामने पेश करेंगे और ऐसा कोशिश करेंगे जिससे ऊख की कीमत दो रुपए फी मन हो जाय।

Mr. Jamuna Prasad Singh: सभापतिजी, मुझे भी इसके बारे में कुछ कहना है। गन्ने की खेती का कानून होते हुए भी गन्नें की खेती का व्यवसाय दिनों दिन खतम होता जा रहा है। इसके कई कारण हैं। किसानों को गन्ने की उचित कीमत नहीं मिलती है। अभी ४ और ५ को लखनऊ में मिटिंग थी। उस मीटिंग में डाक्टर साहब भी गये थे और कई वजहों से वहां हमको भी जाने का मौका मिला था। इसके कानून में कुछ ऐसी अड़चनें हैं जिनकी वजह से गन्ने की खेती की तरक्की बिहार में नहीं हो सकती। पहली बात यह है कि कोई वजह नहीं है कि यू० पी० और बिहार की कमिटी एक

रहे। एक बोर्ड रहने की कोई जरूरत नहीं मालूम होती है। अगर यू० पी और बिहार का एक बोर्ड नहीं रखें तो हम समझते हैं कि आपको ज्यादा सहूलियत होगी। इस विषय पर आगे जब मौका होगा हमारे मिनिस्टर साहब विचार करेंगे। अभी जो कई एक संशोधन (amendment) झूलन बाबू यहां दिये थे.......

Mr. Jhulan Sinha : वे पेश नहीं हुए।

Mr. Jamuna Prasad Singh : खैर, जिन संशोधनों की नोटिस उन्होंने दी थी उनमें भी वही अड़चन हो जाती थी कि बिना यू० पी० गवर्नमेंन्ट से मशविरा किये हम इन्हें मंजूर नहीं कर सकते थे क्योंकि हर बात के लिए हमें यू० पी० गवर्नमेन्ट से सलाह (consult) करना होगा और जिन २ बातों में हमको उसके साथ चलना है विना उनकी मशविरा के चल नहीं सकते। कोई कानून बना नहीं सकते और कोई भी काम गन्ने के मुतल्लिक नहीं कर सकते। कीमत की बात आयी है। यह इतनी बड़ी चीज है कि जिसके बारे में कदम बढ़ाने में बड़े २ विशेषज्ञ (experts) भी थर्राते हैं। डाक्टर साहब यह कोशिश कर रहे हैं कि गन्ने की कीमत दो रुपया से ढाई रुपया जरूर कर दी जाय। लेकिन इसमें बहुत सी अड़चनें हैं। हम एक सुझाव, जिसे मीटिंग में हमने पेश की थी, यहां भी आपके सामने रखना चाहते हैं। वह यही है कि गन्ने की कीमत आप बढ़ा दीजिए, ढाई रुपया कर दीजिए। लेकिन उसकी corresponding scheme जो है जिसके मुताबिक चीनी की कीमत बढ़नी चाहिए; उसे करने की जरूरत नहीं है। यह चीज गैरमुमकीन मालूम पड़ती है लेकिन हम कहते हैं कि जो molasses (शोरगुल) बोलने भी दीजिए आप लोग (हँसी)

हमारा कहना यह था कि जो molasses आप चार आने मन के हिसाब से दे देते हैं उसकी कीमत आप बढ़ा दीजिए, चार पांच रुपया में मिलमालिकों को दे दें। अगर ऐसा कर देंगे तो उनके घाटे की पूर्ति हो जायगी और गन्ने की कीमत बढ़ने पर भी अगर आप चीनी की कीमत नहीं बढ़ाये तो मिलमालिकों को घाटा नहीं होगा क्योंकि molasses जो चार आना मन मिलता है उसे पांच रुपया के हिसाब से दें देने पर उनकी कमी compensate हो जाती है और जो खोंइया है कुछ कीमत पर उनको दे दें। आप जानते हैं कि जलावन

की लकड़ी दो ढाई रुपया मन के हिसाब से बिक रही है और वह भी कन्ट्रोल रेट है। अगर उसका दो ढाई रुपया कन्ट्रोल रेट है तो गल्ले की कीमत, जिसे हम पटाते, कोड़ते और जिसकी हिफाजत करते हैं, डेढ़ रुपया से कम क्यों हो सकती है ? इसलिए खोइया भी जलावन है और उसकी कीमत भी कन्ट्रोल के हिसाब से जो जलावन की कीमत है वही कर दी जाय। अगर ये चीजें हो जायं यानी molasses की कीमत और खोइया की कीमत का कन्ट्रोल कर दिया जाय तो हम समझते हैं कि केतारी की कीमत बढ़ाने पर भी चीनी की कीमत नहीं बढ़ानी होगी और जो मिलमालिक हैं उनको भी घाटा नहीं होगा। इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं और ऐसा करने से गन्ने की खेती जो दबी जा रही है वह दबी नहीं रहेगी और किसानों को जो घाटा पड़ता है नहीं पड़ेगा। हम समझते हैं कि हम लोगों के लिए गन्ने का सवाल एक बड़ा अहम सवाल हो रहा है। हम यह भी चाहते हैं कि इतनी ज्यादा गन्ने की खेती न हो जाय कि गल्ले की पैदावार कम हो जाय। आपको इस तरह का सामंजस्य (balance) रखना चाहिए कि जिसमें केतारी की खेती एकदम गायब न हो जाय, किसानों के लिए यह भी जरूरी चीज है। हमारा कहना है कि पाकिस्तान के जो सब प्रान्त हैं वहां गन्ने की खेती नहीं होती है। हम चीनी से गल्ला बदलना चाहेंगे और जहां तक हम समझते हैं पाकिस्तान भी चीनी लेकर गल्ला देना चाहेगा इसलिए आप जो समझते हैं कि अगर चीनी ज्यादा पैदा कर लेंगे तो गल्ले को घाटा होगा तो ऐसा नहीं होगा। एक मन चीनी के बदले उससे कहीं ज्यादा गल्ला आप पाकिस्तान से ले सकते हैं। ये बहुत से छोटे मोटे सवाल हैं जिनको हम हल कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मिनिस्टर साहब विशेषज्ञों (experts) से सलाह करके जो आगे करना चाहते हैं इस तरह से करेंगे जिसमें गन्ने की खेती की तरक्की हो और घाटा भी न हो।

Sardar Harihar Singh: जनाब स्पीकर साहब, बाबू झूलन सिनहा ने जो सुझाव आज पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूँ। यह निहायत जरूरी है कि गन्ने की कीमत बढ़ा दी जाय। आज जो लोग गन्ने की खेती करते हैं और खास कर दक्षिण बिहार में जो लोग गन्ने की खेती करते हैं उनको इसकी जानकारी है कि गन्ने की पैदाइश बराबर नहीं होती है।

इसलिए हमारे यहां दक्षिण बिहार में जो मिलें हैं उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि हमारी स्थिति कायम रह सकती है या नहीं। उनको खेती में ज्यादा खर्च करना पड़ता है, गन्ने के खेत ज्यादा दिन तक उसी फसल के लिए बझे रहते हैं और उसमें जो पैसा आप देते हैं उसको compensate नहीं कर सकते। इसलिए निहायत जरूरी है कि दो रुपया से कम उसका भाव न हो और हो सके तो ज्यादा भाव रखा जाय। आज यह स्थिति है कि वहां धान गेहूं बो देते हैं और इससे पैदावार हो जाती है उसीसे लाभ होता है। पहले ऊख money crop का काम करता था लेकिन वह स्थान धान का हो जाता है। हम एक गृहस्थ के नाते, अपने देखने के अनुभव से आपसे कहते हैं कि कल जहां गन्ने की खेती होती थी आज धान बोये जा रहे हैं और लोग गन्ने की खेती कम करते जा रहे हैं। इसका नतीजा यह हो रहा है कि हमारे यहां एक मिल बंद हो गयी और जो दूसरी मिलें हैं पूरा काम नहीं कर रही हैं। इसलिए निहायत जरूरी है कि आप अफसरों को हिदायत कर दें कि यह खेती गायब न होने पावे। ऐसा करिये कि सूबे की एक बहुत जबरदस्त खेती सूबे के बाहर न चली जाय, जो इतनी पूंजी लगी हुई है वह कायम रह सके और यहां वाले इससे जो फायदा हो उसे उठा सकें। इसलिए आपकी मारफत मिनिस्टिर साहब का इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि गन्ने की कीमत दो रुपया से कम करने की कोशिश न करें बल्कि इससे बेशी करने की कोशिश करें।

Mr. Muhammad Abdul Ghani :

جناب صدر ' اسی شوگر کنٹرول بل پر اس وقت تک هاؤس میں گنا بونے والوں اور فیکٹری والوں کی داستان جو گنے سے چینی بناتے هیں ' آپکے سامنے رکھی گئی هے - مگر جو چینی استعمال کرتے هیں اُنکے متعلق کوئی سوال نہیں پیش کیا گیا - جس وقت شوگر انڈسٹری کو protection دیا گیا تھا اُس وقت یہ خیال کیا گیا تھا کہ یہ انڈسٹری کچھہ دنوں کے بعد خود اپنے پیروں پر کھڑی هو جائیگی - مگر بد قسمتی سے ابتک جتنے فیکٹری والے هیں انہوں نے کوئی نظم نہیں کیا کہ وہ انڈسٹری اپنے پیروں پر کھڑی هو جائے - اور نہ یہ هوا کہ چینی استعمال کرنے والوں کو چینی سستے داموں پر مل سکے - آج جو پبلک exchequer کا روپیہ اسقدر کم هو گیا هے ' وہ صرف اس وجہ سے هوا کہ شوگر انڈسٹری کو protection دیا گیا -

اب یہ چیز ہاؤس کے سامنے آتی ھے کہ یہ protection دینا continue کیا جائے - لیکن سوال یہ ھے کہ آخر کبتک چینی استعمال کرنے والے نقصان اُٹھاتے رھینگے - اور کبتک فیکٹری والے کے رحم و کرم پر ھم سبلوگ رہینگے اگر فیکٹری والے یہ چاھتے ھیں کہ یہ انڈسٹری self supporting ھو جائے تو انکو ابتک کر لینا چاھئے تھا - اس امر کی طرف حکومت کو دھیان دینے کی ضرورت ھے کہ اگر یہ انڈسٹری self supporting نہیں ھوسکتی ھے تو پھر اُسکو حکومت protection دینا چھوڑ دے کیا ضرورت ھے کہ پبلک exchequer کا اتنا روپیہ اس انڈسٹری کے protection میں خواہ مخواہ خرچ ھو • دوسری جگہ سے اگر چینی آئیگی تو سستے داموں پر یہاں مل سکیگی - اسکے علاوہ custom duty سے بھی اُس حالت میں حکومت کو کافی روپیہ ملیگا -

Mr. Harvans Sahay : ; हाशयजी, इस बिल में जो statement of objects and reasons हैं उसके आखिरी Paragraph में यह लिखा हुआ है कि चीनी की Industry की हालत बहुत ही चिन्ताजनक है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे साथी इस पर गैर मामूली तौर से ध्यान दें। Sugar Factory Control Act बने हुए आज दस वर्ष हो गये। अभी जो बिल पेश किया गया है उसमें सन १९४० से १९४९ तक और खास करके ६३ धारा की सरकार ने जो अमेन्डमेन्ट इस पर किये हैं, उन सब को इकट्ठा कर दिया गया है। अभी इस बिल पर गौर से ख्याल करें तो मालूम होगा कि असली कानून जो चिन्ता और फिकिर की चर्चा है वह इस बिल से मेरे ख्याल से दूर नहीं होती है। इसको दूर करने के लिए आपको गैर मामूली तरीके से काम करना होगा। आपको इस पर सोचना चाहिए कि जो अमेन्डमेन्ट आपने पेश किया है उसको किस तरह से काम में लाया जाय जिससे आपकी चिन्ता कुछ हद तक दूर हो जाय। हम देखते हैं कि तीन जरूरी बातें इसमें दी गयी हैं। पहला Sugar Commission, दूसरा Variety Committee और तीसरा ऊख को Co-operative system से supply करना है। अभी जो बिल है वह Sugar Factories के लिए Penal Code है। इसमें ज्यादातर यही है कि Factory फलां जुर्म करेगा तो सजा होगी। यह काफी नहीं है और इससे आपका काम नहीं चलेगा। आपको यह देखना है कि जितने फैक्टरी हैं उनके requirement का ५० प्रतिशत भी पूरा नहीं होता है, उसको किस तरह से

पूरा किया जाय। यह दशा इसलिए है कि जो ऊँख की खेती करते हैं उनको इससे नफा नहीं है। किसी भी किसान को तीन फसल मार कर ऊँख की खेती करनी पड़ती है, दो भदई और एक रब्बी। इन तीन फसल के बदले उसको एक फसल ऊँख की मिलती है। एक एकड़ जमीन में अगर ऊँख की फसल अच्छी हुई तो इस वक्त की कीमत से उसको करीब ३३/४ सौ रुपये मिलते हैं। इसमें दो सौ रुपया तो महज बीज, सिंचाई, छिलाई इत्यादि में खर्च हो जाते हैं। बाकी रहा १३/४ सौ, इसमें मजदूरी, खाद, कोराथी वगैरह सब मिली हुई हैं। अब आप एक एकड़ जमीन में एक फसल में आठ मन भी रख लें तो तीन फसल में २४ मन गल्ला होता है क्योंकि तीन फसल मार कर एक फसल ऊँख की होती है। अब आप अगर गल्ले की कीमत को जोड़ें तो सब खर्च काटने पर भी किसान को ऊँख ऊपजाने के बजाय गल्ला ऊपजाने से दुगना लाभ होता है।

The Hon'ble the Speaker : किसान को तो शायद आमदनी से मतलब है।

Mr. Harivans Sahay : अभी जो कीमत आप दे रहे हैं उससे किसान यह हरगिज नहीं चाहता है कि वह ऊँख की खेती करे।

Mr. Prabhu nath Sinha : आपके कहने का मतलब यह है कि ऐसा उपाय किया जाय जिससे Industry भी चले और किसान को भी फायदा हों।

Mr. Harivans Sahay : हां, इस लिए मैं कहता हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि ऊँख की फैक्टरी को काफी ऊँख मिले तो आप ऊँख की कीमत बढ़ाइये। दो रुपया मन ज्यादा नहीं है। आप यदि इस Industry को बिहार से भगा देना चाहते हैं तब तो दूसरी बात है। नहीं तो, हिसाब जोड़ कर देखिये कि ऊँख उपजाने वाले को ऊँख उपजाने में नफा है या गल्ला उपजाने में। यदि आप चाहते हैं कि फैक्टरी भी कायम रहे और किसान भी कायम रहें तो आपको ऊँख की कीमत को बढ़ाना ही होगा। ऊँख की फैक्टरी के कायम रहने के लिए उसकी requirement के मुताबिक उसे ऊँख मिलनी चाहिए और किसान को कायम रखने के लिए उसें जायज पैसे मिलने चाहिए जिससे उसे ऊँख उपजाने में घटी नहीं हो। अभी आप देखते हैं कि छ सात

साल से फैक्टरियों के requirement के मुताबिक उनको ऊँख नहीं मिलती है और इसकी खास वजह ऊँख की कीमत की कमी है। अगर ऐसी हालत रही तो ज्यादा दिन नहीं लगेगा कि ऊँख की मिलें इस प्रान्त को छोड़ कर भाग जायेंगी। जब तक उनकी requirement पूरी नहीं होगी तब तक वे कैसे रह सकती हैं? हमारे जिले में एक फैक्टरी है जिसकी requirement ४२ लाख मन है, लेकिन उसने इस साल सिर्फ १८ लाख मन crush किया है तो उस फैक्टरी की क्या हालत होगी? किस तरह से वह कायम रह सकती है? अगर इस तरह की हालत रही तो खतरा है कि यह Industry इस प्रान्त से चली जायगी। इसलिए हम आप से यह दरखास्त करते हैं कि आप भी इस बात पर जोर दें कि ऊँख की Industry को बचाने के लिए ऊँख की कीमत बढ़ायी जाय।

एक दूसरी बात जिसके बारे में हमारे यमुना बाबू ने कहा है वह मुलैसेज के बारे में है। यह इन्साफ की बात नहीं है कि फैक्टरी उसको चार आने मन बेचे और बाहर वह आठ रुपये मन बेचा जाय।

Dr. Purna Chandra Mitra: १४ रुपये मन बिकता है।

Mr. Harivans Sahay: खैर, १४ रुपये मन हमारे यहाँ नहीं बिकता है। जहां चार आना मन रखा है वहां चार रुपए मन रखा जाना चाहिए। एक मन मुलैसेज में बाइस रुपये की शराब बनायी जाती हैं। कहाँ बाइस रुपये मन और कहां चार आने मन। ये तो फैक्टरियों के लिए ही बदनसीबी नहीं है बल्कि किसानों के लिए भी बदनसीबी है। ऐसा करने से तो सिर्फ नशाखोरों को और शराबखोरों को प्रोत्साहन देना होगा। इसलिए मैं आपका इस तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि आप इस चीज पर बहुत गौर से देखें और विचार करें और ऐसा इन्तजाम करें जिससे फैक्टरी वालों को भी फायदा हो और किसानों को भी नफा हो।

The Hon'ble the Speaker: मुलैसेज के बारे में आपको दूसरे मिनिस्टर साहब से कहना चाहिए।

Mr. Harivans Sahay : यहां पर इसका प्रसंग आ गया इसलिए मैंने यहां इसका जिक्र कर दिया। मेरा कहना सिर्फ यही है कि आपको कीमत को बढ़ाने में जोर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी जरूरियात हैं जिनको आप दूसरे ऐक्ट में पूरा कर सकेंगे। तबतक आप ऊख की कीमत बढ़ाने की तरफ ध्यान दें जिससे ऊँख की पैदावार बढ़ सके। जबतक आप ऊख की कीमत नहीं बढ़ायेंगे तबतक ऊख की पैदावार नहीं बढ़ा सकते हैं। न कि फैक्टरियां ही चल सकती हैं नाहीं किसान इस तरफ तवज्जह दे सकते हैं कि गन्ने की पैदावार बढ़ाया जाय।

The Hon'ble the Speaker : संक्षेप में होना चाहिये।

Mr. Murli Manohar Prasad : Sir, I should have liked to record a silent vote in the discussion of this Bill, but certain observations made by my friend Mr. Abdul Ghani obliged me to participate in the debate I should like to point out that my friend Mr. Abdul Ghani is entirely wrong in stating that protection to the sugar indutry was granted merely in the interest of the sugar industry. If you will read the report of the Tariff Board that first considered the question of the grant of protection to the sugar industry you will find that the Tariff Board definitely state that protection has to be granted not so much in the interest of the industry as in the interest of the agriculturists in order to provide them with a money crop. Sir, the fact remians that it is not merely the industry but I think several lakhs of cultivators have been benefited by protection granted to the sugar industry. When I speak of matters relating to the sugar industry I mean the millions in Bihar who depend on sugarcane for their money crop. Sir, it is true that the industry has not been doing as well as it might have. But I should like to point out that the fault does not lie entirely with the ministry and I beg of the members to remember the date when the cultivators of this province not merely depended on the sugarcane for the money crop but also on the industry. India, as you know, is the largest sugar producing country in the world and Bihar is the second largest sugar producing province in this country and sugar industry is the second largest national industry in India. That is the position and, therefore, we must be very careful when we discuss important questions

such as whether protection should be continued to the industry or not in a half-hearted manner. It is not true that the protection is being granted only in the interest of the sugar industry. Sir, if the industry has not been doing as well as it might have you must remember that the fault does not lie entirely with the Government. For some years the industry sufferred from over production of sugarcane. Government policy was one of the ascillations and oscillations. Ultimately when the industry was doing well the point was that it was suffer ing from non-production of sugarcane You will be astounded to know the figures of production as they have been recorded from time to time. The sugar industry in India recorded a record production of 13 lakhs tons some times ago.

It has come down to 9 lakhs tons and I should like the House to appreciate the difficulty with which the country is confronted in the matter of sugar prices. Sugar prices are based on a calculation of many factors. Not the least among them is the number of crushing days for which a factory is able to work. The calculation was based on the crushing season of about 100 days The crushing season has actually come down to nearly 50 to 60 days and the prices remain the same. As a matter of fact, I may tell you that the sugar price, as it obtains to day, is absolutely uneconomic and in order to increase the number of crushing days, the industry in fact has been ready, has been willing, has been anxious to pay a larger price to the cane growers. I do not think they have been anxious to pay higher prices out of altruistic motive, but sheer self-interest has determined their interest and whereas they have been anxious to pay a higher price, it is Government that have stood in the way and Government will not listen to any proposal to make the sugarcane price commensurate to the cost involved. In, regard to the price at the same time, we must bear in mind that fault is not of the Bihar Ministry or of the Bihar Government either. I know the Bihar Ministry have fought out for a higher price for the cane growers but as things stand at present. the sugarcane prices are ultimately fixed by the Government of India and the Government of India have their reasons of their own for insisting on a lower price for sugarcane. I can well appreciate what brings them to take the attitude that they have taken. But I should

like to appeal to the Hon'ble Minister in charge of the Bill to record a strong protest against the Government of India's persistent interference in the matter of fixation of price for sugarcane. After all Bihar is very, very greatly interested not merely in a large number of cane-growers but also in sugar industry and therefore the Bihar Government must insist that it is for them to determine what exactly the price should be not merely in the interest of the industry but also in the interest of the cane-growers. It is true, as you remarked a little while back, that the growers are after all in the interest that their crops carry. That is perfectly true. Prices of food crops are bound to fall sooner than later. I believe and I will not be surprised if there is a slump in prices of food grains before long. Therefore when the despression comes, it is again the sugarcane that will stand the growers in good stead and therefore we cannot afford to take any risk so far as sugarcane prices are concerned. The price that is now being paid to the cane-growers is absosolutely niggardly, it is not economic, it is unremunerative and non competitive and therefore it is necessary in the interest of cane-growers, leave alone the industry, that the Bihar Government should insist that they must have the fullest freedom of action in the matter of fixation of price for sugarcane. Sir, I congratulate the Hon'ble Minister for having brought forward this measure. This measure was a necessity, but I should like very respectfully to point out that I am disappointed at the Bill, as it stands. For after all the Ministry has been in office for a year and a half and it should have been possible before now to have brought forward a comprehensive measure in the light of experience gained in the working of the sugarcane industry. It was many months back that the Hon'ble Minister inaugurated a Cane-growers' Conference at Patna At that time the Conference had promised to convene a smaller conference to discuss the problems relating to sugar industry. That conference was held many months ago, I believe. Surely, Sir, it should have been possible for you to bring up a fore comprehensive Bill during the many months that have elapsed. After all you are to fight out the Sugarcane Control Act in this province. The Act has been beneficial to the growers. I have no doubt and in my opinion the Act was a necessity. It has served a useful purpose, but

I do feel that so far as you are concerned, the problems relating to sugar industry are neither new nor novel and this matter of prices and the situation that confronts the sugar industry have been before the province for over a year and a half and I do think that it should have been possible to bring forward by now a much more comprehensive Bill than the one that is in our hands to-day. However, it is no use weeping over split milk. I am glad to learn from the Hon'ble Minister that he is proposing to appoint a committee to consider ways and means for the improvement of the industry. I hope the work of the committee will be expedited and during the next session of the Assembly, it should be possible for Government to introduce a thorough going measure which will deal effectively with the problems relating to sugar industry One last word and I have done. My hon'ble friend, Mr. Ghani is chary with the continuance of protection to the sugar industry and he has found fault with the Government of India for having given the protection. In his opinion the industry has not been able to stand on its own legs. In the first place, it is not correct that the industry has not been able to stand on its legs. If the industry has not, the reasons thereof are well-known I should like to inform Mr. Ghani that this is not the line of argument that should be adopted. I should tell you that England has gone out of her way to grant protection, very substantial protection, to the beet sugar industry, knowing full well after the full and complete investigation by the Royal Commission that the beet sugar industry cannot be successful, cannot be remunerative, cannot compete with the sugar industry of other countries but because the beet sugar industry is entirely an English concern—I am sorry I have not got the figures......

The Hon'ble the Speaker :—The figures are not required.

Mr. Murli Manohar Prasad : I have not got them with me. The figures will show that very, very substantial protection in the form of subsidies and in various other ways is being given to the beet sugar industry, because it is essentially a British concern.

Mr. Muhammad Abdul Ghani : How long ?

Mr. Murli Manohar Prasad: Let us not be light-hearted in our treatment relating not merely to the continuance of large national industries but an industry which affects millions of people on the country side of the province.

The Hon'ble Dr. Saiyid Mahmud:

حضور والا - میں نے تقریریں آنریبل ممبروں کی غور سے سنی زیادہ تر جو باتیں کہی گئی ہیں وہ شوگر کی قیمت کے متعلق ہے سر دست میں زیادہ نہیں کہہ سکتا ہوں سوا اسکے کہ میں ممبروں کو نہیں دلانا چاہتا ہوں کہ جہانتک بہار گورنمنٹ کا تعلق بہار گورنمنٹ قیمت کے متعلق جتنا ممکن ہوگا پوری کوشش کریگی - ممبروں کی اسپیچوں سے معلوم ہوا ہے کہ وہ ارکھ کے قیمت کے متعلق بہت سخت رائے رکھتے ہیں - کیا آنریبل ممبروں کی خواہش ہے کہ میں انکی خواهش جو Sugar-cane price کے متعلق ہے گورنمنٹ اوف انڈیا کو convey کردو (بہت سی آوازیں - ضرور ضرور) بہتر ہے -

بہر حال price کے متعلق جہانتک ممکن ہوگا بہار گورنمنٹ کوشش کریگی ممبروں کو معلوم ہونا چاہئے کہ یہ گورنمنٹ اوف انڈیا کے ہاتھہ میں ہے اسکے علاوہ اور اور بھی بہت سی باتیں کہی گئی ہیں اور مولوی محمد عبد الغنی نے جو باتیں کہی ہیں ان سب کا جواب کافی طور سے بابو مرلی منوہر پرشاد نے دیدیا ہے میں اسکو دوہرانا نہیں چاہتا ہوں جو باتیں مرلی بابو نے کہی ہیں وہ صحیح ہیں اس انڈسٹری کی حالت جتنی اس صوبہ میں خراب ہے مجھے خوب معلوم ہے لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرونگا کہ رول اور ایکٹ کے revise کرنے کے لئے کمیٹی نہیں بنائی گئی اسلئے حالت خراب ہے لیکن میں کہہ چکا ہوں کہ کمیٹی کا خیال ہمیں پہلے ہی تھا میں نے تہارگمنٹ سے کہا تھا کہ یہ رول و ایکٹ revise کرنیکی ضرورت ہے لیکن مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے کہ چونکہ ہملوگوں کو آئے ہوئے ڈیڑھہ برس ہوا اور اس درمیان میں Rule and Regulation کو revise نہیں بنائے جاسکے اسلئے شوگر انڈسٹری کی حالت خراب ہوئی وہ درست ہوسکتی ہے اسوقت جو حالت خراب ہے وہ کسی بے قاعدگی کی وجہ سے یا رول کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے اسکے بہت سے وجوہ ہیں اسکی وجہ مرلی بابو کو معلوم ہے اسلئے جو وجوہ ہیں اور جو حالت ہیں انکو درست کرنا ضروری ہے اسطرف زیادہ توجہ انڈسٹری کی حالت درست کرنے پر دی گئی ہے اسلئے ایک کمیٹی بنادی ہے سومبار کو ناموں

کا علان ضرور کر دونگا - چند بھائیوں نے ملاسز molasses کے بارے میں فرمایا ھے میں
آپکو اطلاع دیتا ہوں کہ گورنمنٹ نے molasses کو تی کنٹرول اش ہرست کیا ھے باقی
کے متعلق Cane Excise Commissioner Department Secretary
اور دوسرے افسران اس پر غور کر رھے ھیں اور کمیٹی جو بنی ھے اسبات کو طے کریگی
اور اسکے مطابق عملی جامہ پہنایا جائیگا - وسٹلری اور الکوھل کے لئے مولسز کی
ضرورت ہوگی تو اسکی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد جو بچیگا تی کنٹرول ہو جائیگا -
جہانتک شوگر انڈسٹری کو مدد دینے کی ضرورت ھے میں اسکا اسوقت کل فیکٹریاں
شوگر کی نقصان اٹھارھی ھیں مگر خاصکر ساؤتھ بہار کی شوگر انڈسٹری زیادہ نقصان
اٹھارہی ھے شبھہ ھے کہ شاید یہ دو برس تک Continue کر سکے گورنمنٹ اوف
بہار نے جو ڈیڑھ آنہ نیا ٹیکس ان پر لگایا تھا اسمیں سے ۲ پائی معاف کردیا ھے
تمام فیکٹری کو اور وہ پیسہ واپس کردیا گیا لیکن ساؤتھ بہار کے فیکٹریوں کے کل
پورے ٹیکس ایک آنہ ۲ پائی واپس کر دینے کی تجویز کر دیا ھے اسطرحسے قریب
۱۴ لاکھ روپیہ شوگر فیکٹریوں کو واپس کر دیا گیا ھے - بہار گورنمنٹ کو جس حد
تک مدد کر سکتی تھی اس نے کیا گو اسکا مطالبہ ھے کہ گزشتہ سال کا کل ٹیکس
واپس کر دیا جائے لیکن بہار گورنمنٹ کے امکان میں نہیں تھا - ھمارے دوستوں
کو معلوم ہونا چاھئے کہ گزشتہ سال گورنمنٹ اوف انڈیا نے تجویز کی تھی کہ ایک
روپیہ سے زیادہ price نہیں ہو لیکن بہار گورنمنٹ کے کوشش کرنے پر اور یوپی -
گورنمنٹ کے راضی ہونے پر سوا روپیہ price (1-4-0) طے ہوا اسلئے بہار گورنمنٹ
ان انڈسٹریوں کو rehablitate کرنے کیلئے جو بری حالت میں ھیں انکو مدد
کرنیکی جس حد تک ممکن تھا کوشش کیا اور آئندہ بھی بہت کوشش کرنیکا ارادہ
رکھتی ھے لیکن مشین (Growers) کو ھر غلے سے کافی آمدنی ہوتی ھے اسلئے وہ
اوکھہ پیدا کرنا چھوڑ دیا ھے جسقدر اوکھہ بویا جاتا ھے اسکا گڑ بناتے ھیں اور اسمیں
انکو زیادہ نفع ہوتا ھے وہ خود ھی گڑ crush کرکے بیچ دیتے ھیں اسلئے اوکھہ
فیکٹریوں میں دینا نہیں چاھتے ھیں فیکٹریوں کو اوکھہ زیادہ نہیں ملتا ھے -
برس در برسوں سے یہ فیکٹریاں کام نہیں کر سکتی ھیں تو انکو encourage کرنے
کیلئے حکومت کی یہ تجویز ھے یہ price attractive کر دیا جائے تاکہ
Cane growers زیادہ تعداد ھی اونکھہ فیکٹریوں کو دے سکیں - یہاں پر جو
نمائندہ ھیں انکو معلوم ہونا چاھئے کہ مرلی بابو اسکی طرف اپنے اسپیچ میں اشارہ
کیا ھے - لیکن میں اُمید کرتا ہوں کہ بہت دنوں تک یہ حالت نہیں رھیگی جسے

قسمت میں depration ہو جائیگا ممکن ہے کہ دو ایک ہی برسوں میں ہو - جب imflamation ختم ہو جائیگا تو شوگر ہی ایک ایسا crop رہجائیگا جو money crop ہوگا اسوقت بہت زیادہ فائدہ ہوگا - اس اوکھہ کے زریعہ سے بڑی تعداد سے کروروں پیدا کیا ہے اور خوشحال ہوئے ہیں اور جب غلوں کی قیمت گھٹنے لگے گی تو خود محسوس کرینگے اور آخر میں یہی چیزونکے فائدہ بخش ہونگی کہولنے ضرورت ہے کہ اسطرف وہ ابھی سے توجہ کریں - Cane growers کو لازم ہے کہ وہ اسکو نہ چھوڑیں اب اس سے زیادہ ہمارے خیال میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے - میں آنریبل ممبروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بغیر بحث مباحثہ کے اس تجویز کو پاس کرنیکی اجازت دیدی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھہ تبدیلی کی ضرورت اور میں بھی سمجھتا ہونکہ ضرورت ہے تو آپ لوگ مہربانی کرکے جلد از جلد دوسرے session میں اپنے قیمتی تجویزوں کو پیش کر دیں جس حد تک اس انڈسٹری کو درست کرنے میں بہار گورنمنٹ کو مدد دینے کی ضرورت ہوگی وہ کی جائیگی - میں ان چند الفاظ کے ساتھہ دوبارہ آپ صاحبوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں -

The Hon'ble the Speaker : The question is :

That the Bihar Sugar Factories Control (Second Amendment) Bill, 1947, be passed.

The motion was adopted.

THE BIHAR WAQF BILL, 1946. (BILL NO. 18 OF 1946.)

The Hon'ble Dr. Saiyid Mahmud : Sir, I beg to move :

That the amendments made by the Legislative Council to the Bihar Waqfs Bill, 1946 (as passed by the Assembly) be taken into consideration.

Mr. Muhammad Abdul Ghani:—

(*Rose to speak.*)

The Hon'ble Dr. Saiyid Mahmud :

جناب والا ' زرا مجھے اس بد قسمت بل کے متعلق کچھہ عرض کرنا ہے consideration کے لئے جب بل لے لیا جائے تو میں کہوں -